

गोरखपुर के निवर्तमान सांसद योगी आदित्यनाथ जी के दूसरे कार्यकाल की कुछ अतिविशिष्ट उपलब्धियाँ एक नजर में

1. चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में :

- (i) बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर की मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारण मान्यता समाप्ति के आदेश को निरस्त कराकर उसे बहाल कराना।
- (ii) गोरखपुर जिला चिकित्सालय (जनरल एवं महिला) के जीर्णोद्धार के लिए उत्तर प्रदेश हेल्थ डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत 7.50 करोड़ रूपया स्वीकृत कराना।
- (iii) सम्बन्धित विधानसभाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना।
- (iv) श्री गोरक्षनाथ मन्दिर परिसर में गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय की स्थापना जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी प्रायः सभी विभाग और उपकरण उपलब्ध है तथा रोगियों को अत्यन्त सस्ते दर पर परामर्श, उपचार और सेवा उपलब्ध होती है।

2. दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्र में :

- (i) दूरदर्शन केन्द्र गोरखपुर के लिए आवासीय व्यवस्था एवं पुराने उपकरणों की जगह नये उपकरण लगाने हेतु 5.60 करोड़ रूपये स्वीकृत कराना।
- (ii) आकाशवाणी केन्द्र गोरखपुर के लिए एफ. एम चैनल स्वीकृत कराना।

3. रेल सेवा के क्षेत्र में :

- (i) गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए "गोरखधाम एक्सप्रेस" तथा "सप्तक्रान्ति एक्सप्रेस" गाड़ियों का संचालन।
- (ii) गोरखपुर से मुम्बई के लिए "गोदान एक्सप्रेस" का संचालन।
- (iii) गोरखपुर से दूर्ग तथा हरिद्वार के लिए गाड़ियों का संचालन।
- (iv) गोरखपुर रेलवे स्टेशन का माडल स्टेशन के रूप में विकास कराना।
- (v) गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उत्तर दिशा से भी प्रवेश द्वार तथा कम्प्यूटरीकृत टिकट कउण्टर की व्यवस्था कराना।
- (vi) गोरखपुर सिटी हाल्ट को पूर्ण स्टेशन के रूप में गोरखपुर सिटी स्टेशन के नाम से विकसित करना तथा नकहा स्टेशन का उच्चीकरण।
- (vii) गोरखपुर से सहजनवां तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण स्वीकृत कराना जिसमें डोमिनगढ़ से गोरखपुर के बीच कार्य प्रारम्भ।
- (viii) गोरखपुर से पिपराइच घुघली छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन।
- (ix) गोरखपुर-नौतनवा-गोण्डा लूप लाइन के आगमन परिवर्तन का कार्य प्रारम्भ कराना।
- (x) गोरखपुर-लखनऊ के बीच इण्टरसिटी ट्रेन का संचालन कराना।

4. सड़क यातायात एवं परिवहन के क्षेत्र में :

- (i) गोरखपुर महानगर में धर्मशाला बाजार में ओवरब्रिज स्वीकृत कराकर कार्य प्रारम्भ करवाना।
- (ii) राप्ती नदी पर बने वर्तमान राजघाट सेतु के बगल में नये सेतु के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत कराकर कार्य प्रारम्भ कराना।
- (iii) गोरखपुर महानगर में यातायात समस्या के समाधान तथा बाढ़ बचाव हेतु हावर्ट तथा माधवपुर बन्धों का उच्चीकरण कराकर इसे रिंग रोड के रूप में विकसित कराना।
- (iv) गोरखपुर के बाहरी भाग में चार लेन के एक बाई पास रोड तथा राप्ती नदी पर एक अन्य चार लेन के सेतु हेतु 400 करोड़ रुपये स्वीकृत कराना।
- (v) मानीराम तथा सजहनवां विधान सभा को जोड़ने के लिए गोवरहिया नाले तथा मानीराम व पिपराइच को जोड़ने के लिए चिलुआ नाले पर 1-1 करोड़ की लागत से पुलों का निर्माण कराना।
- (vi) नगर क्षेत्र में डोमिनगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ने के लिए रोहिन नदी पर एक पीपे के पुल का निर्माण कराना।
- (vii) कौड़िया ब्लाक में डोहरिया जगत बेला के बीच बढनी में तथा दहला घाट पर बाढ़ में बह गये पुलों की जगह नये पुलों का निर्माण करवाना।

5. वायु सेना के क्षेत्र में :

- (i) चौदह वर्षों से बन्द पड़ी वायु सेवा को पुनः शुरू कराकर गोरखपुर को लखनऊ, नई दिल्ली और कोलकाता से जोड़ना।
- (ii) गोरखपुर से काठमाण्डू (नेपाल) तक हवाई सेवा प्रारम्भ कराने के लिए अनवरत प्रयास तथा जुलाई 2004 से सेवा प्रारम्भ होने की आश्वासन।

6. विद्युत सेवा के क्षेत्र में :

- (i) ताला विद्युत परियोजना के अन्तर्गत भूटान से नई दिल्ली के लिए 1000 मेगा वाट की लाइन का 400 के.बी.ए. का एक सब स्टेशन गोरखपुर के लिए स्वीकृत कराकर 65 करोड़ रुपये अवमुक्त करवाना।
- (ii) संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विधान सभाओं के 100 गाँवों में विद्युतीकरण।

7. बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में :

- (i) प्रायः प्रतिवर्ष गोरखपुर महानगर एवं आस-पास के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ की विभीषिका से स्थायी बचाव हेतु 100 करोड़ रुपये की लागत से राप्ती बेसिन परियोजना स्वीकृत करवाना।
- (ii) महानगर को बाढ़ से बचाने के लिए हावर्ट तथा माधवपुर बांध का उच्चीकरण।

8. उद्योग के क्षेत्र में :

- (i) गोरखपुर को उत्तरी भारत का वस्त्र उद्योग सम्बंधी प्रमुख केन्द्र बनाने के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में पावरलूम सर्विस सेन्टर की स्थापना करवाना।
- (ii) गोरखपुर को टेक्सटाइल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 'टेक्सटाइल सेन्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट स्कीम' टी.सी.आई.डी.एम. के अन्तर्गत पावरलूम पार्क तथा हथकरघा विकास एवं डिजाइन केन्द्र के रूप में घोषित कवाना।

- (iii) गोरखपुर में पावरलूम इकाईयों को आधुनिक मशीनरी के लिए 50 लाख रुपये तक कर्ज लेने की सुविधा दिलाना और सीधी सब्सिडी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करवाना।
- (iv) पावरलूम कारीगरों के लिए नयी सामूहिक बीमा योजना लागू करवाना जिसके अन्तर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 80,000 रुपये तथा प्राकृतिक मृत्यु होने पर 50,000 रुपये बीमा प्राप्त होगा। इसमें सालाना प्रीमियम बड़ा हिस्सा केन्द्र सरकार तथा जीवन बीमा निगम की ओर से भरा जायेगा।
- (v) हथकरघा बनकर परिवारों के लिए आर्टीजन क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ करवाना जिसके अन्तर्गत 1.25 करोड़ आर्टीजन तथा हथकरघा बुनकर परिवारों को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध प्राप्त हो सकेगा।

9. शिक्षा के क्षेत्र में :

- (i) गोरखपुर में दो नये केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना।
- (ii) सहजनवां में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना।
- (iii) गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 38 कक्षाएँ, हॉल, पुस्तकालय वाचनालय का निर्माण तथा कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा।
- (iv) मूक बधिर एवं अन्ध विद्यालय में जीर्णोद्धार एवं विकास।

10. डाकघर एवं दूरभाष सुविधा के क्षेत्र में :

- (i) संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में 10 नये डाकघरों की स्थापना।
- (ii) संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में 15 नये दूरभाष एक्सचेंजों की स्थापना तथा 5 एक्सचेंजों का उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण।

11. जन सुविधाओं के विकास के क्षेत्र में :

- (i) गोरखपुर बस स्टेशन तथा गोरखपुर जंक्शन, रेलवे स्टेशन एवं अन्य अनेक सार्वजनिक स्थानों पर पथिक निवासी का निर्माण।
- (ii) चन्द्रलोक कुष्ठाश्रम, राजेन्द्र नगर कुष्ठाश्रम तथा गोरखपुर सेन्ट्रल जेल में चहार दीवारी प्रतीक्षा कक्ष और जन सुविधाओं का विकास।
- (iii) गोरखपुर महानगर में कलेक्ट्री बार एसोसिएशन, कमिश्नरी बार एसोसिएशन, सिविल बार एसोसिएशन, विश्वकर्मा मन्दिर (जटाशंकर) में पुस्तकालय, वाचनालय तथा शेड आदि का निर्माण।
- (iv) संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में डोहरिया शहीद स्मारक स्थल (पाली विकास खण्ड) और सहजनवां तहसील के समीप वाचनालय तथा पुस्तकालय, झुंगिया तथा जंगल बहादुर अली शेखपुरवा (चरगावां विकास खण्ड) में व्यायामशाला, साखी तथा हिरुआ (जंगल कौड़िया वि.ख.) गाँव में यात्री विश्रामगृह, बास स्थान (भटहट वि.ख.) में धर्मशाला, ग्राम सभा सरहरी (जंगल कौड़िया वि.ख.) में तथा ग्राम प्रानपुर (सहजनवां वि.ख.) में यात्री विश्रामगृहों का निर्माण।
- (v) संसदीय क्षेत्रान्तर्गत गोरखपुर महानगर में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा महेबा चुंगी मेडिकल कालेज गेट, सहजनवां तहसील के समीप झुंगिया चरगावां सहित अनेक स्थानों पर सुलभ शौचालयों का निर्माण।

गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की चिरलम्बित कुछ प्रमुख समस्याएँ इनके समाधान की दिशा में सांसद योगी आदित्यनाथ की भूमिका

लोक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन समस्याओं का अन्त नहीं है और इस बात में भी सन्देह नहीं है कि इन समस्याओं से जूझ कर इन्हें समाधान तक पहुँचाने से जहां व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता का मूल्यांकन होता है वहीं वर्तमान एवं भविष्य के विकास का रास्ता भी खुलता है। इसलिये कृत्तित्ववान व्यक्ति समस्याओं से आँख चुराने या पलायन करने के बजाय उनको चुनौती के रूप में स्वीकार कर समाधान के लिये प्रयत्नशील रहता है। व्यक्तिगत समस्याओं से लोग खुद भी यथाशक्ति जूझते हैं किन्तु एक जन-प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं से चाहे वे सार्वजनिक हों, चाहे मतदाताओं की व्यक्तिगत समस्याएं हो बराबर दो चार होना पड़ता है और लोग उससे अपेक्षा करते हैं कि वह प्रतिनिधि होने के नाते उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन से लेकर संसद से सड़क तक सुलझावे। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के निवर्तमान सांसद योगी आदित्यनाथ जी ने जब दूसरी बार 1999 में हुए संसदीय चुनाव में पुनः विजयश्री प्राप्त कर भारतीय संसद में प्रवेश किया तब इस संसदीय क्षेत्र की कई चिरलम्बित समस्याओं के समाधान की नैतिक और प्रतिनिधि होने के कारण कर्तव्यपरक जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गयी। उनके प्रमाणित पराक्रम और कृत्तित्व से लोगों की अपेक्षाएं जगीं और उनसे अपेक्षा की जाने लगी कि वे क्षेत्र की कुछ चिरलम्बित प्रमुख समस्याओं का अपने दूसरे कार्यकाल में प्राथमिकता के साथ समाधान करेंगे। क्षेत्र की कुछ समस्याएं 1998 में जब योगी आदित्यनाथ जी प्रथम बार भारतीय संसद में सबसे कम उम्र के एक सांसद के रूप में चुने गये थे उसके पूर्व से लम्बित थी और बारहवीं लोकसभा के 13 महीनों के अति संक्षिप्त कार्यकाल में योगी जी की पहल के बावजूद इनका सम्पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पाया था। दूसरी बार प्रतिनिधि चुने जाने पर उन्होंने पुनः बिना समय गवाये उन सभी समस्याओं के यथा सम्भव समाधान का बीड़ा उठा लिया और ईमानदारी तथा गम्भीरता से जनता सहित शासन प्रशासन का बीड़ा उठा लिया और ईमानदारी तथा गम्भीरता से जनता सहित शासन प्रशासन के सहयोग से काफी हद तक अपने प्रयत्नों में उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त की। कम उम्र से ही सांसद के रूप में चुने जाने पर लोगों को लगता था कि योगी आदित्यनाथ जी के मार्ग में अनुभव की कमी स्वाभाविक रूप से आड़े आवेगी किन्तु क्योंकि यशस्वी और तेजस्वी पुरुष अपने कृत्तित्व और पुरुषार्थ के लिये उम्र के मोहताज नहीं होते इसलिये योगी आदित्यनाथ जी ने भी थोड़े समय में अपनी स्वयं स्फूर्त सेवाभावना पर दुःख कातरता, कर्मठता तथा सूझ-बूझ के बल पर सभी आशंकाओं को निर्मूल करते हुए संसद और क्षेत्र में भी अपने कर्तृत्व की ऐसी धाक जमा दी जिससे न केवल गोरखपुर की तमाम लम्बित समस्याओं का समाधान आसान हो गया बल्कि हर आम व खास व्यक्ति को यह भली-भाँति एहसास हो गया कि उसे योगी आदित्यनाथ जी के रूप में एक चिर-प्रतीक्षित अनमोल रत्न मिल गया है जो हर आंधी तूफान में, विकट से विकट परिस्थितियों में अपने सुख-दुःख व आराम की चिन्ता किये बिना उनके साथ खड़ा हुआ है। यद्यपि समाचार पत्रों के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी के भगीरथ प्रयत्नों द्वारा गोरखपुर क्षेत्र की तमाम चिरलम्बित समस्याओं के समाधान की थोड़ी बहुत जानकारी सबको अवश्य हुई होगी तथापि वर्षों से जन-मानस को मथ रही समस्याओं के समाधान में निवर्तमान सांसद की भूमिका और उपलब्धियों का प्रमाणित तथ्यपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना, आम लोगों को इसकी पूरी जानकारी देना, अत्यन्त आवश्यक है ताकि जनता और मतदाता अपने प्रतिनिधि के कृत्तित्व को, उसकी उपलब्धियों को न केवल सही रूप में जाने-पहचाने बल्कि विरोधियों के दुष्प्रचार का भी पर्दाफाश हो सके। इसी प्रयोजन से संक्षेप में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की कुछ चिरलम्बित समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके समाधान के लिये यहाँ के निवर्तमान सांसद योगी आदित्यनाथ जी के प्रयत्नों से मिले परिणामों का यथा सम्भव विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है :

गीडा के विकास की समस्या :

नोएडा की तर्ज पर गोरखपुर को भी औद्योगिक विकास की उपलब्धियों से विकसित करने के उद्देश्य से गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत सहजनवां विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए 1990 में औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की स्थापना की गयी। इसके लिये शासन के निर्देश पर प्रशासन में नेवास, झुगियां, बड़गहन, कालेसर एवं जुड़ियान गाँवों में स्थित किसानों की 172.68 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था। स्थापना काल के समय से ही किसानों को उनकी अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा न मिलने के कारण जन-आन्दोलनों की वजह से गीडा का अपेक्षित विकास बाधित रहा। सांसद के रूप में अपने 13 महीनों के प्रथम कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी ने सफलता पूर्वक प्रशासन और किसानों के बीच समझौता कराकर मुआवजा सम्बन्धी चिरलम्बित विवाद का समाधान कराया था और तब यहाँ योजनानुसार औद्योगिक इकाईयों के लगाने का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। इस दिशा में क्षेत्रीय सांसद योगी आदित्यनाथ जी और कुछ करते इसके पूर्व ही 13 महीनों में 12वीं लोकसभा भंग हो गयी और फिर कुछ समय के लिये औद्योगिक इकाईयों का गीडा में स्थापित होना अवरूद्ध हो गया। सांसद के रूप में योगी जी के दूसरे कार्यकाल में पुनः गीडा क्षेत्र के विकास की समस्या सामने आयी जिसके समाधान के बिना नोएडा की तर्ज पर गोरखपुर के औद्योगिक विकास का सपना साकार नहीं हो सकता था। इसलिये योगी जी ने जन-प्रतिनिधि होने के नाते इस ओर प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया। इसलिये चूंकि बुनियादी सुविधाओं और पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में उद्योगपति इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयाँ लगाने को तैयार नहीं थे इसलिये पहली आवश्यकता यह थी कि उन्हें आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का स्पष्ट आश्वासन दिया जाय और वहाँ के वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाया जाय। ऐसी स्थिति में योगी जी ने जहाँ एक ओर प्रयास कर गोरखपुर के उद्योगकर्मियों को वांछित भरोसा दिया वहीं दूसरी ओर शासन और प्रशासन से बराबर सम्पर्क व संपर्ष कर गीडा के औद्योगिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। योगी जी के प्रयत्नों से उत्तरी भारत में वस्तु उद्योग के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में गोरखपुर को विकसित करने के लिये केन्द्र सरकार के सहयोग से 44 लाख की लागत से एक "पावरलूम सर्विस सेन्टर" की स्थापना हुई तथा गोरखपुर का टेक्सटाईल्स सिटी के रूप में विकसित करने के लिये "टेक्सटाईल सेन्टर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट स्कीम" के अन्तर्गत इसे पावरलूम पार्क तथा हथकरघा विकास और डिजाईन केन्द्र के रूप में केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्री सैयद शाहनवाज हुसैन से घोषित कराया। तदनुसार गीडा में 80 एकड़ भूमि में 18 करोड़ की लागत से टेक्सटाईल उद्योग के विकास हेतु स्थापना विकसित करने के लिये "नार्दन इण्डिया टेक्सटाईल एसोशियेशन" ने एक योजना तैयार की है जिससे यहाँ पर 300 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होगा तथा हजारों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा इससे उत्साहित होकर गोरखपुर के कई उद्योगपतियों ने अपनी कई छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाईयाँ गीडा में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है जिससे वहाँ उत्तरोत्तर विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हमें विश्वास है कि योगी जी के प्रयत्नों से गोरखपुर को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने का सपना शीघ्र ही पूरा हो जायेगा।

धर्मशाला बाजार (गोरखपुर महानगर) रेलवे पुल के ऊपर ओवरब्रिज बनाने की समस्या :

गोरखपुर महानगर के धर्मशाला बाजार में मेडिकल कालेज रोड पर सड़क के ऊपर रेलवे का एक छोटा सा डाट का पुल है। पुल की निचाई के कारण उसके नीचे की जमीन भी दोनों तरफ की सड़कों से नीची है जिसके कारण आये दिन यहाँ अक्सर तीन से चार फुट पानी लग जाता है जिससे घंटों यातायात बाधित हो जाता है और यात्रियों व नागरिकों को आने-जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि मुख्य नगर को रेलवे लाईन के उस पार बसे भाग से जिसमें राष्ट्रीय कालोनी के सभी फेज, मेडिकल कालेज, चरगावा, दूरदर्शन केन्द्र, पादरी बाजार, फातिमा अस्पताल, गीता

वाटिका व पिपराईच आदि कई महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं - जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग है जिस पर जल-जमाव के कारण अक्सर जाम लग जाता है और लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यह महानगर में यातायात की एक बड़ी समस्या है जो वर्षों से नागरिकों की जर्बदस्त चिन्ता का कारण बनी रहा है किन्तु आश्वासनों के बावजूद महानगर की इस चिरलम्बित यातायात समस्या का समाधान करने के लिये योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल से पूर्व कोई सार्थक पहल नहीं हो पायी थी। मार्च 1998 में योगी आदित्यनाथ जी पहली बार गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय संसद के लिये चुने गये तब जन-प्रतिनिधि होने के कारण यह विकट समस्या उनके सामने भी आयी और उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार इसे पूरी गम्भीरता से राज्य व केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया। बात अभी प्रारम्भिक सफलताओं के बावजूद पूरी तरह परवान नहीं चढ़ी थी कि 12वीं लोक सभा तेरह महीनों में भंग हो गयी। पुनः 13वीं लोक सभा में निर्वाचित होने पर सांसद के रूप में अपने दूसरी कार्यकाल में उन्होंने फिर इस समस्या को गम्भीरता से उठाया और 18 अक्टूबर 2001 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ-सिंह जी ने धर्मशाला ओवरब्रिज का नया शिलान्यास किया और तद्नन्तर शीघ्र ही ऊपरिसेतु का निर्माण शुरू हो गया। शिलान्यास के बाद भी ओवरब्रिज के लिये समय-समय आवश्यक धन अवमुक्त कराने के लिये भी योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ और दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ी किन्तु इनका अदम्य उत्साह अन्तः सफल हुआ और शनैः शनैः आवश्यक धन की अपेक्षा पूर्ण होने पर क्रमशः काम बढ़ता हुआ अब अन्तिम चरण में है। इस प्रकार धर्मशाला पर ओवरब्रिज बनवाने की समस्या जिससे महानगर की जनता विगत कई दशकों से परेशान हो रही थी सांसद के रूप में योगी जी के दूसरे कार्यकाल की उल्लेखनीय उपलब्धि बनकर हमारे सामने प्रस्तुत है।

बाबा राघव दास मेडिकल कालेज की मान्यता समाप्ति की समस्या :

वर्ष 1998 में इण्डियन मेडिकल कौंसिल ने बाबा राघव दास मेडिकल कालेज गोरखपुर की एम०बी०बी०एस० उपाधि की मान्यता को समाप्त करने की सिफारिश सरकार से की क्योंकि कौंसिल द्वारा उक्त डिग्री के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार बाबा राघव दास मेडिकल कालेज में -

1. शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त हैं।
2. विभिन्न विभागों में लिपिक, टाइपिस्ट और स्टेनों के भी बहुत से पद रिक्त हैं।
3. नर्सों की संख्या भी मानक से काफी कम है।
4. छात्रावासों की संख्या और स्थिति मानक के अनुरूप नहीं है।

ज्ञातव्य है कि मेडिकल कालेज की उपर्युक्त कमियों की ओर मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया ने कई बार सर्व सम्बन्धित का ध्यान आकृष्ट किया था किन्तु उत्तरदायी लोगों ने कभी कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जिसके कारण आई०एम०सी० को विवश होकर उक्त कठोर सिफारिश करनी पड़ी। मान्यता समाप्ति की उक्त सिफारिश से बी०आर०डी० मेडिकल कालेज की एम०बी०बी०एस० डिग्री की मान्यता खतरे में पड़ गयी और यहां उक्त डिग्री के लिये अध्ययनरत छात्रों/छात्राओं के साथ मेडिकल कालेज का भविष्य भी अन्धकारमय हो गया। गोरखपुर से उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में अनेक कैबिनेट और राज्यमंत्री थे, विधायकगण भी थे किन्तु जब एक दो अपवादों को छोड़कर किसी से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला तब सभी प्रभावित लोग हार-थक कर सांसद योगी आदित्यनाथ जी के पास आये इन्होंने संकट की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल व्यक्तिगत रुचि लेकर इण्डियन मेडिकल कौंसिल और राज्य तथा केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया। योगी जी ने सर्व सम्बन्धित को पत्र लिखकर एवं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी समझाया कि मेडिकल कालेज की कमियों के लिये वहां के अधिकारी

व विद्यार्थी जिम्मेदार नहीं है इसलिये उनका भविष्य क्यों अधर में डाला जा रहा है और मानक की जिन कमियों के कारण मान्यता समाप्त करने की सिफारिश मेडिकल कौंसिल ने की है उन्हें सरकार ही पूरा कर सकती है। अतः मानक के अनुसार सरकार अपेक्षित कमियां दूर करें तथा जब तक कमियां दूर न हो जाये कालेज की मान्यता बहाल रखें। योगी जी ने इस संबंध में व्यापक जन-जागरण अभियान चलाकर मेडिकल कालेज तक पदयात्रा भी की जिसका दबाव राज्य सरकार और उसके अधिकारियों पर पड़ा। अवश्य है कि मेडिकल कालेज में मान्यता समाप्ति का यह संकट एक बार नहीं दो-दो बार गहराया और दोनों ही बार गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ जी ने सड़क से संसद तक अथक प्रयत्न कर मेडिकल कालेज की डिग्री की मान्यता बहाल रखी। सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ जी के दूसरे कार्यकाल की यह एक और बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे मेडिकल कालेज के कर्मचारी, छात्र/छात्राएं ही नहीं पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस भू-भाग सहित इससे लगे बिहार और नेपाल की सीमावर्ती के क्षेत्र की जनता ने भी राहत की सांस ली।

गोरखपुर महानगर में राप्ती नदी पर एक और सड़क पुल के निर्माण की समस्या :

गोरखपुर से वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, बिहार और असम आदि राज्यों की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 28 एवं 29 पर गोरखपुर महानगर में राप्ती नदी के ऊपर एक सड़क पुल 1964 में बना था। तब से इस मार्ग पर जनसंख्या वृद्धि के साथ ही यातायात का दबाव बहुत बढ़ चुका है इतना ही नहीं वर्तमान सड़क पुल पुराना भी पड़ चुका है और इसमें जगह-जगह दरारें भी आ गयी है जो खतरे को लक्षित करती हैं। यातायात में भारी वृद्धि के कारण अब इसका आकार-प्रकार आवागमन की दृष्टि से न तो पर्याप्त है न ही सुरक्षित। ऐसी स्थिति में इस पुल के जीर्णोद्धार के साथ ही इसके बगल में साथ-साथ एक और सड़क सेतु बनाने की महती आवश्यकता थी ताकि यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ उनका गमनागमन भी सुगम हो। पुराने पुल के जीर्णोद्धार एवं नये पुल के निर्माण की आवश्यकता तो लोग असें से महसूस कर रहे थे और समाचार पत्रों में जब-तक इस आशय की मांग भी की जाती थी किन्तु इस समस्या को पूरी गम्भीरता से योगी आदित्यनाथ जी ने ही जब 1998 में पहली बार वे सांसद चुने गये थे उठाया और मुख्य मंत्री राज्य सरकार के पी०डब्ल्यू०डी० मंत्री तथा केन्द्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्री के समक्ष और यथा अवसर संसद में भी जोरदार ढंग से इस समस्या को प्रस्तुत किया। योगी जी के अथक परिश्रम से न केवल राजघाट पर बने पुराने सड़क पुल के जीर्णोद्धार के लिये चौसठ लाख नब्बे हजार रुपये मिले बल्कि एक नये सड़क पुल की मांग भी सरकार द्वारा स्वीकृत कर इसे बजट में शामिल कर लिया गया। 1999 में लोक सभा भंग हो गयी जिसके कारण सड़क पुल का यह स्वीकृत प्रस्ताव ठण्डे बस्ते में चला गया लेकिन सदा जनहित के कार्यों में रुचि रखने वाले गोरखपीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ जी जो कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ते इसलिये जब दूसरी बार 1999 में गोरखपुर से पुनः सांसद के रूप में निर्वाचित हुए तो उन्होंने फिर इस दिशा में प्रयत्न शुरू कर दिये और अन्ततः लम्बी जद्दोजहद के बाद उनके प्रयत्नों से 410 मीटर लम्बे 9 स्पैन के दो लेन और कुल चालीस हजार पी०सी०यू० क्षमता वाले नये सड़क पुल का शिलान्यास 25 जनवरी 2004 को विधिवत सम्पन्न हुआ। यह पुल वर्तमान के बगल में कुछ ही मीटर की दूरी पर बनना शुरू हो गया है और इसका कार्य सम्पत्ति युद्ध स्तर पर चल रहा है। सांसद के रूप में योगी जी के दूसरे कार्यकाल की यह भी एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जिसका लाभ केवल गोरखपुर ही नहीं अपितु राजमार्ग संख्या 28 एवं 29 पर यात्रा करने वाले सभी लोगों को होगा।

भारत नेपाल सीमा पर आई०एस०आई० और तस्करी की बढ़ती गतिविधियों की समस्या :

भारत-नेपाल सीमा पर गोरखपुर महाराजगंज सहित सभी सीमावर्ती जनपदों और कस्बों में पाकिस्तान की खुफिया

संस्था आई०एस०आई - जो भारत में तोड़-फोड़ और आतंकवाद की कार्रवाइयों को प्रोत्साहित तथा सिमी आदि के सहयोग से प्रायोजित करती है की बढ़ती हुई गतिविधियां पूरे देश के लिये चिन्ता का विषय है। क्षेत्र के भौतिक विकास के साथ-साथ हिन्दुत्व और हिन्दुस्तान के हितों के लिये निरंतर चिन्तित और संघर्षरत रहने वाले सांसद योगी आदित्यनाथ जी का ध्यान भी अपने संसदीय क्षेत्र की सीमाओं से लगे क्षेत्रों में आई०एस०आई० की बढ़ती गतिविधियों की ओर आकर्षित हुआ। क्योंकि इन सीमावर्ती क्षेत्रों से न केवल राष्ट्रविरोधी गतिविधियां संचालित होती हैं बल्कि मादक द्रव्यों, नकली नोटों और नेपाली लड़कियों सहित गो-वंश की तस्करी भी बड़े पैमाने पर होती है इसलिये उन्होंने पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थान-स्थान पर घूमकर, जन सभाएँ कर जहां जनता को इस संकट से अवगत और जागृत किया वहीं संसद और सरकार को भी इसकी पोखता जानकारी दी। उन्होंने बताया लगभग 853 किमी० लम्बी भारत नेपाल सीमा के दोनों तरफ की पट्टियों पर पांच हजार से अधिक मस्जिदें और मदरसे बन चुके हैं जिनमें इबादत और पढ़ाई कम राष्ट्रविरोधी गतिविधियां अधिक संचालित होती हैं। उनके और जनता के दबाव पर शासन प्रशासन ने इसकी जांच करायी और सरकार को सीमा पर निगरानी और निगबानी बढ़ानी पड़ी। विगत कुछ वर्षों से नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से मादक द्रव्यों, नकली नोटों और नेपाली लड़कियों की तस्करी भी बड़े पैमाने पर हो रही है जिससे भारत नेपाल का संबंध, नैतिकता और भारतीय अर्थव्यवस्था सभी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विभिन्न हिन्दू संगठनों ने इस सीमावर्ती संकट की ओर अपने आन्दोलनों के माध्यम से इतनी जोरदार आवाज उठायी कि उसकी अनुगूँज सड़क से संसद तक पहुंची और अन्ततः सरकार को विवश होकर सामान्य पुलिस के हाथ से बार्डर की देख-रेख एवं सुरक्षा वापस लेकर एस०एस०बी० को सौंपना पड़ा। तब से निश्चित रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में आई०एस०आई की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर ही नहीं तस्करी पर भी पर्याप्त अंकुश लगा है जिसका सारा श्रेय योगी आदित्यनाथ जी को है। यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के संदर्भ में उनके दूसरे कार्यकाल की एक और बड़ी उपलब्धि है।

दूरदर्शन केन्द्र गोरखपुर और उसके कर्मचारियों के लिये आवास निर्माण की समस्या :

गोरखपुर महानगर में नवम्बर 1984 में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना हुई थी। स्थापना के कुछ समय बाद ही इस केन्द्र के लिए 84 लाख रुपये की लागत से राप्ती नगर बस डिपो के सामने 3-4 एकड़ भूमि खरीदी गयी थी। भवन निर्माण हेतु टेण्डर भी निकला था किन्तु इसके बाद तब से वर्षों तक यहां दूरदर्शन केन्द्र के निजी कार्यालय तथा कर्मचारियों के लिये आवासी सुविधा के निर्माण की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई और दूरदर्शन केन्द्र पूर्ववत् किराये के भवन में सुविधाओं की कमी के कारण प्रभावित गुणवत्ता के साथ चलता रहा। महानगर की तमाम चिरलम्बित समस्याओं की तरह इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर भी दूरदर्शन केन्द्र गोरखपुर के कर्मचारियों, कलाकारों और नगर के कई प्रबुद्ध नागरिकों ने अपने प्रतिनिधि सांसद कर्मचारियों, कलाकारों और नगर के कई प्रबुद्ध नागरिकों ने अपने प्रतिनिधि सांसद योगी आदित्यनाथ जी का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्र के साथ अब तक हुए सौतेले व्यवहार और भूमि खरीद के बावजूद भवन निर्माण की उपेक्षा किये जाने की ओर संसद का तथा सम्बन्धित मंत्रालय के मंत्रियों और अधिकारियों का भी ध्यान आकृष्ट किया। इस बीच तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवेधनाथ जी महाराज से मिलने तथा श्री गोरक्षनाथ जी का दर्शन करने गोरखपुर आये। उनके यहां प्रवास के समय भी योगी आदित्यनाथ जी ने किराये का जीर्ण-शीर्ण भवन में किसी तरह चले रहे गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्र के अहम मामले को उठाया। अन्ततः उन्हें अपने सत्प्रयास में अपेक्षित सफलता मिली और सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री श्री नकवी ने 1 जुलाई 1998 को पहले से ही एतदर्थ खरीदे गये भूखण्ड पर गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्र के निजी भवन का चला आ रहा गतिरोध